हिमाचल प्रदेश विधान सभा

11.00 बजे पूर्वाह्न राष्ट्रगान गाया गया।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

ओम्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतं गमय। ओम् शांति।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं बहुत ही सम्मानित सभी सदस्यगण,

1. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभालने के पश्चात् पहली बार इस विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं, समस्त प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष के प्रथम सत्र और 12वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 11वें सत्र के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।

2. राज्य में हाल ही में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए मैं प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। यह गौरव का विषय है कि राज्य में पंचायती राज संस्थानों के कुल प्रतिनिधियों में लगभग 58 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है।

3. मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों की प्रगति, समृध्दि और बेहतरी के लिए कार्य

कर रही है तथा राज्य के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आज सभी स्वीकार करते है कि मेरी सरकार ने लगभग सभी चुनावी वायदों को पूरा कर लिया है तथा सरकार द्वारा अर्जित उपलब्धियां मेरी सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का साक्ष्य है। मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।

4. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछ़डा वर्ग, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। सामाजिक सुरक्षा पैंशन को ब़ढाकर 600 रुपये प्रतिमाह किया गया है और 80 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग अथवा 70 प्रतिशत से अधिक की अपंगता वाले व्यक्तियों को यह पेंशन 1100 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अन्तर्गत 3,39,921 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं और इस वर्ष इस प्रयोजन पर 306.43 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

5. लाभार्थियों को नए आवास के निर्माण के लिए मेरी सरकार 75,000 रुपये तथा आवास के रख-रखाव के लिए 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। इस वर्ष 3080 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 23.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

6. प्रदेश के आवासहीन लोगों की आवासीय आवश्यकताएं पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 1,280 आवास स्वीकृत किए हैं।

इसके अतिरिक्त, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत भी 2,128 आवास मंजूर किए गए हैं।

7. महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए मेरी सरकार नें इस वित्त वर्ष 375.52 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। ''बेटी है अनमोल'' योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति राशि को 300 रुपये से 1500 रुपये प्रति वर्ष से ब़ढाकर 450 रुपये से 2250 रुपये प्रति बच्चा किया गया है। शिमला के निकट मशोबरा में 6.16 करोड़ रुपये की लागत से ल़डकियों के लिए मॉडल चिल्ड्रन होम का निर्माण किया जा रहा है।

8. इस वित्त वर्ष के दौरान 4,45,997 बच्चों, 1,00,789 गर्भवती माताओं एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाओं तथा 1,37,931 किशोरियों को एकीकृत बाल विकास योजना के दायरे में लाया गया है। बाल/बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को प्रथम अप्रैल, 2015 से 500 रुपये से ब़ढाकर 2300 रुपये प्रति बच्चा, प्रति माह किया गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को हमीरपुर जिला में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 5832 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए 2.95 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

9. स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान राशि पर वर्ष 2015-16 के दौरान 3 करो़ड 56 लाख 98 हजार 210 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों की पुत्रियों एवं पौत्रियों के विवाह पर क्रमशः 51,000 और 21,000 रुपये की दर से विवाह अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

10. द्वितीय विश्व युध्द के सैनिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को प्रथम अप्रैल, 2015 से 2000 रुपये से ब़ढाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं/बच्चों को 12 करो़ड रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। शहीद सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को मई, 2015 से ब़ढाकर 5 लाख रुपये किया गया है।

11. शिक्षा क्षेत्र मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सभी को शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने 21 नए प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष के दौरान 49 प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशाला, 92 माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च पाठशाला और 58 उच्च पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत किया गया। सात नए महाविद्यालय और एक ललित कला महाविद्यालय भी इस अवधि में खोले गए। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 878 पद सृजित किए गए। सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों के 535 पद भरे हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण पर 67.50 करो़ड रुपये की धनराशि व्यय की जा रही है।

12. इस वर्ष 6 नए आई.टी.आई. खोले गए। अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सरकारी आई.टी.आई की सुविधा उपलब्ध है। ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग सामुदायिक महाविद्यालय ने मंडी जिला के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, सुंदरनगर के परिसर में कार्य करना आरम्भ कर दिया है। राजकीय

इंजीनियरिंग महाविद्यालय, ज्यूरी कोटला की सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कक्षाएं जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुंदरनगर में आरम्भ कर दी गई हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान की कक्षाएं भी सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में फिलहाल अस्थायी परिसर में सितम्बर, 2015 से आरम्भ कर दी गईं हैं।

13. सोलन जिला के बद्दी स्थित सेंट्रल इंस्टीटयूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टैक्नालोजी (सी.आई.पी.ई.टी.) तथा शिमला जिला के महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जुंडला में भी वर्ष 2015 में कक्षाएं आरम्भ की गईं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना को एन.आई.टी हमीरपुर के परिसर से क्रियाशील किया गया है।

14. मेरी सरकार ने इस वर्ष 13 नए आदर्श विद्यालय स्थापित किए हैं। गुणात्मक सुधार प्रणाली के समुचित कार्यान्वयन के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है। वर्तमान में, एक राज्य विश्वविद्यालय, एक निजी विश्वविद्यालय, 17 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों और 18 निजी महाविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के साथ प्रत्यायित किया गया है।

15. विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 11 राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 67,619 विद्यार्थियों को 13.64 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत भी 1,30,213 विद्यार्थियों को 62.03 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। महात्मा गांधी वर्दी योजना के अन्तर्गत 7,31,122 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने

के लिए 52.00 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा रही है।

16. समाज के कमज़ोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठयक्रमों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। राज्य में मंद दृष्टि व बधिर बच्चों के लिए दो विशेष पाठशालाएं क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से उन्हें 10वीं कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

17. माननीय सदस्यगण, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 8 नए नागरिक अस्पताल, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 उप-स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। सरकार प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में रोगियों को 56 प्रकार की औषधियां और 10 उपभोगीय निःशुल्क आबंटन कर रही है। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार ने 266 नए चिकित्सक, 15 विशेषज्ञ चिकित्सक और 25 दंत चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त, पैरा-मेडिकल स्टाफ के 167 पद भरे गए तथा 516 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

18. क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में पी.पी.पी. पद्वति के अन्तर्गत अत्याधुनिक सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में अलग से आपातकालीन चिकित्सा विभागों का सृजन किया है।

19. मेरी सरकार ने तीन नये स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए आवश्यक संकाय सदस्यों और सहायक स्टाफ के पद सृजित किए हैं। इन महाविद्यालयों का नामकरण डॉ. वाई.एस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चम्बा तथा डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर के रूप में किया गया है।

20. चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षक संकाय की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने संकाय सदस्यों की सेवानिवृति की आयु प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर 62 वर्ष से ब़ढाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

21. मेरी सरकार ने इस वर्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञों सहित 47 पद और पैरा-मेडिकल स्टाफ के 39 पद भी भरे हैं। आयुष चिकित्सा पध्दति को प्रचलित करने और लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाने के लिए वर्ष 2015-16 में किन्नौर जिला के पूह, सांगला और रिकांगपियो तथा कुल्लू जिला में 4 निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से 1688 रोगियों का उपचार किया गया। वर्ष 2015-16 में 43 आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थानों के भवनों का निर्माण पूरा किया गया।

22. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य के 36.82 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 31 दिसम्बर, 2015 तक 18,27,900 राशनकार्ड धारकों को 3,81,918 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया।

23. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आने वाले गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को सरकार प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। इस पर आने वाली अतिरिक्त लागत राज्य सरकार ही वहन कर रही है। सरकार जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है तथा गैर-जनजातीय क्षेत्रों में सभी ए.पी.एल परिवारों को 14 किलोग्राम गेहूँ का आटा तथा 6 किलोग्राम चावल प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है।

24. मेरी सरकार राज्य विशेष उपदान योजना के अन्तर्गत सभी राशन कार्ड धारकों को निर्धारित दरों पर तीन दालें, दो खाद्यान्न तेल और एक किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध करवाने के लिये कृतसंकल्प है। इस वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 210 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

25. मेरी सरकार ने प्रथम मई, 2015 से कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिये दिहा़डी की दरों को 170 रुपये से ब़ढाकर 180 रुपये तथा अंशकालीन कर्मचारियों की दिहा़डी 21 रुपये से ब़ढाकर 22.50 रुपये प्रति घण्टा की गई। अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को भी 1500 रुपये से ब़ढाकर 1700 रुपये प्रति माह किया गया है।

26. अंशकालीक कार्यकर्ताओं, अनुबन्ध कर्मचारियों और दिहाड़ीदार/कन्टीन्जेट पेड श्रमिकों को नीति के अनुसार नियमित किया जा रहा है। आयुर्वेदिक प्रवक्ताओं की अनुबन्ध राशि को 15,300 रुपये से ब़ढाकर 19,125 रुपये प्रति माह किया गया है।

27. सरकारी महिला अनुबन्ध कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को 112 दिनों से ब़ढाकर 135 दिन किया गया है। दन्त स्वास्थ्य विभाग में दन्त विशेषज्ञों के अनुबन्ध वेतनमान को 26,250 रुपये से ब़ढाकर 40,000 रुपये किया गया। अनुबन्ध पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों को 25 प्रतिशत की दर से एनपीए प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मानदेय को भी 5000 रुपये से ब़ढाकर 7000 रुपये प्रति माह किया गया है।

28. आऊटसोर्स आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को राज्य के भीतर दैनिक भत्ता 130 रुपये तथा राज्य के बाहर 200 रुपये प्रतिदिन की दर से प्रदान किया जा रहा है। गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता भी 260 रुपये से ब़ढाकर 280 रुपये किया गया हैं।

29. विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के मानदेय में 20 प्रतिशत वृध्दि की गई है। सिविल सेवाओं की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

30. स्थायी तौर पर परिवार नियोजन के उपाय अपनाने पर इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृध्दि की गई है। एक कन्या शिशु होने के उपरांत परिवार नियोजन उपाय अपनाने पर प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये से ब़ढाकर 35,000 रुपये तथा दो कन्याओं पर 20,000 रुपये से ब़ढाकर 25,000 रुपये की गई है।

31. मेरी सरकार ने पैंशन धारकों और परिवार पैंशन धारकों के लिये मंहगाई भत्ता राहत को 100 प्रतिशत से ब़ढाकर 107 प्रतिशत तथा 107 प्रतिशत से ब़ढाकर 113 प्रतिशत किया है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिये सरकार ने अटल पेंशन योजना अपनाई है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी 1000 रुपये वार्षिक का अंशदान सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

32. मेरी सरकार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है । अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 1220.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ''मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना'' के अन्तर्गत 12.60 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल वाले दो गांवों के एकीकृत विकास के लिए 10.00 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। कुल योजना आवंटन में से 9 प्रतिशत जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष में इस उपयोजना के अन्तर्गत 432 करो़ड रूपये की धनराशि का उपयोग किया जा रहा है ।

33. मेरी सरकार ने इस वर्ष किसानों को 1,10,500 क्विंटल बीज, 167 मीट्रिक टन कीटनाशक और 1,05,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध करवाई। सरकार के निरंतर प्रयासों से इस वर्ष खाद्यानों और सब्जियों का उत्पादन क्रमशः 16.19 लाख और 14.80 लाख टन होने का अनुमान है।

34. पॉलीहाऊस के निर्माण के लिए मेरी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में ''डॉ. वाई.एस परमार किसान स्वरोज़गार योजना'' लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत 111.19 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 1,250 पॉलीहाऊसों का निर्माण किया गया। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को 85 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

35. किसानों को लाभान्वित करने के लिए ''मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर म़जदूर जीवन सुरक्षा योजना'' और ''उत्तम चारा उत्पादन योजना'' नामक दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान सरकार ने किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान के साथ 14,000 क्विंटल विकसित चारा बीज और 3,599 चारा काटने की मशीनें आवंटित कीं। ''राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना'' के अन्तर्गत 150 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अधीन लाया गया है, और इस पर प्रदेश के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। जैविक कृषि को ब़ढावा देने के उद्देश्य से किसानों को केंचुआ खाद इकाइयां स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में 20,000 केंचुआ खाद इकाइयां स्थापित की गईं हैं तथा इस वर्ष 3200 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को जैविक कृषि के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

36. माननीय सदस्यगण, प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न फलों की खेती के अन्तर्गत लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 800 हैक्टेयर क्षेत्र को पुष्पोत्पादन के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

37. वर्ष 2015 के रबी के मौसम में 97,246 किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दायरे में लाया गया। सरकार ने 25 प्रतिशत प्रीमियम अनुदान के तौर पर 9.22 करोड़ रुपये का अंशदान दिया। इस अवधि में 92,423 किसानों के 34.50 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया गया। मौसम आधारित फसल बीमा योजना का विस्तार सभी फल उत्पादक क्षमता वाले खण्डों तक किया गया है। वर्ष 2015-16 में फल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 'मंडी मध्यस्थता योजना' के अन्तर्गत 23.42 करोड़ रुपये मूल्य का 36033 मीट्रिक टन 'सी' ग्रेड सेब खरीदा गया।

38. सरकार द्वारा उच्च किस्म के फूलों और सब्जियों के संरक्षित उत्पादन को विशेष महत्व दिया जा रहा है तथा इस उद्देश्य से 69,198 वर्गमीटर क्षेत्र को ग्रीन हाऊस/शेड नेट हाऊस के अन्तर्गत लाया गया। बागवानी फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए 7,54,158 वर्ग मीटर क्षेत्र को एंटी हेलनेट के अन्तर्गत लाया गया है। यांत्रिक कृषि को ब़ढावा देने के लिए 2253 ऊर्जा संचालित उपकरण अनुदानित दरों पर वितरित किए गए हैं। वर्ष 2015-16 में 600 हैक्टेयर क्षेत्र को सेब पुःनर्जीवन परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। इस वर्ष 16135 किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

39. पशु पालन क्षेत्र के अन्तर्गत ऊना और बिलासपुर जिलों में दो नए पॉलीक्लिनिक अधिसूचित किए गए हैं। शिमला जिला के घणाहट्टी और कांग़डा जिला के पालमपुर स्थित तरल नाईट्रोजन संयंत्रो में कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध करवाने पर 6.07 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पशुओं के निःशुल्क टीकाकरण और दवाइयां उपलब्ध करवाने पर प्रदेश के पशु चिकित्सा

संस्थानों के माध्यम से 13.74 करोड़ रुपये व्यय किए गए। सहकारी सभाओं के माध्यम से दूध प्रसंस्करण एवं अभिशीतन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

40. प्रदेश में गौ-सदनों की स्थापना और इनकी कार्य पध्दति के विनियमन के लिए हिमाचल प्रदेश गौवंश संवर्ध्दन बोर्ड का गठन किया गया है। इस उद्देश्य के लिए 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

41. प्रदेश में 11,557 लोग मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं और दिसम्बर, 2015 तक 58.22 करोड़ रुपये मूल्य की 6636.88 मीट्रिक टन मछलियों की पैदावार की गई। मत्स्य पालक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सभी 11,557 मत्स्य पालकों को शामिल किया गया है।

42. चरागाहों के रख-रखाव के लिए 131 हैक्टेयर वन भूमि पर चारा प्रजातियों का रोपण किया गया है। प्रदेश में वानरों की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए 10 जनवरी, 2016 तक आठ वानर बंध्यीकरण केंद्रों पर 1,02,870 वानरों का बंध्यीकरण किया गया। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वानरों को नाशक जीव घोषित करने और इनके निर्यात से संबंधित मामला प्रभावशाली तरीके से भारत सरकार से उठाया गया है।

43. मेरी सरकार लैंटाना घास से प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वर्ष 2015-16 में 13,000 हैक्टेयर वन भूमि को लैंटाना मुक्त किया गया, जिस पर 19 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त, 13 करोड़ रुपये

के निवेश से 45 लाख औषधीय पौधे रोपे गए। वनों में आग की घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद के सहयोग से अग्नि चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है।

44. मध्य हिमालयी जलागम विकास परियोजना और स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर 108.05 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं तथा 806 पंचायतों के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।

45. प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार नें इस वर्ष मनरेगा के अन्तर्गत 147.78 लाख श्रम दिवस सृजित कर 3,76,245 घरों को रोजगार उपलब्ध करवाया।

46. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 4.87 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार से 17 कौशल विकास प्रोजेक्टों के लिए आजीविका कौशल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मु0 166.49 करोड़, का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

47. मेरी सरकार 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबध्द है। 14वें वित्तायोग द्वारा हस्तांतरित धनराशि के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त 195.39 करोड़ रुपये की धनराशी को पंचायतों में आबंटित किया गया है, ताकि वे अपने क्षेत्र में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें।

48. महिला सशक्तिकरण के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में महिला ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है।

49. स्वच्छ पेयजल और सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना मेरी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। शेष बची 21,450 बस्तियों में से इस वर्ष 1332 बस्तियों को पेयजल योजना की सुविधा प्रदान की गई।

50. प्रदेश के 9 कस्बों में समन्वित विकास और त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का सम्वर्ध्दन किया जा रहा है तथा 2 कस्बों में पेयजल योजनाओं का सम्वर्ध्दन राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा रहा है। लोगों की पेयजल की मांग के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नवम्बर, 2015 की अवधि तक 16,881 हैंडपंप स्थापित किए गए।

51. प्रदेश में ब़डी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 45.00 करोड़ रुपये तथा लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 152.81 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इस वित्त वर्ष 2044 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, 2500 हैक्टेयर क्षेत्र को कमांद क्षेत्र विकास जल प्रबंधन के अन्तर्गत लाया गया है।

52. बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ऊना में 922 करोड़ रुपये की लागत से स्वां नदी और जिला कांग़डा में 180 करोड़ रुपये की लागत से छौंछ खड्ड के

तटीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस वित्त वर्ष में 934 हैक्टेयर क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया है।

53. प्रदेश में आज 34,133 किलोमीटर लम्बी वाहन योग्य स़डकों का जाल बिछ चुका है। वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न योजनओं के लिए आबंटित कुल 826.82 करोड़ रुपये की धनराशि में से दिसम्बर, 2015 तक 342.05 करोड़ रुपये व्यय किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम स़डक योजना के अन्तर्गत 3318 बस्तियों को स़डकों की सुविधा प्रदान की गई है।

54. महत्वपूर्ण स़डक मार्गों और पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड को 543.43 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई है। नाबार्ड ने 92 स़डकों और 15 पुलों के लिए 385.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जिनमें से 31 दिसम्बर, 2015 तक 90.85 करोड़ रुपये व्यय किए गए। दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्गों के रख-रखाव पर 106 करोड रुपये व्यय किए गए।

55. प्रदेश की कुल 3243 पंचायतों में से 3117 पंचायत मुख्यालयों को स़डक की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इसके अतिरिक्त, 93 अतिरिक्त स़डक परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। गांवों को पक्के रास्तों से जोडनें के लिए प्रदेश में ''मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना'' भी कार्यान्वित की जा रही है।

56. प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने तथा निवेश को ब़ढावा देने के उद्देश्य से नियमों का सरलीकरण किया गया हैं। दिल्ली में 5 और 6 अक्तूबर, 2015 को आयोजित 'इन्वेस्टर मीट' में 2724.33 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को अंतिम

रूप दिया गया। इनमें 5800 व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करने की संभावना है।

57. बद्दी में 8.10 करोड़ रुपये के निवेश से ''दक्षता विकास केंद्र'' स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष ऊना जिले के बाथू में 4.46 करोड़ रुपये की लागत से श्रमिक आवास का निर्माण किया गया है, जिसमें 96 लोगों के रहने की सुविधा उपलब्ध है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की क्षेत्रिय शाखा शिमला को 'हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान' मशोबरा के परिसर से आरम्भ किया गया है।

58. प्रदेश में वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खनन के बारे में सुझाव के लिए पहली बार राज्य स्तरीय खनिज सलाहकार समिति का गठन किया गया है। अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) तथा खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2015 में क़डे दण्डात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया है।

59. राज्य ने अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में 10,264 मैगावाट विद्युत का दोहन किया है, जिसमें से 830 मैगावाट का दोहन इस वित्त वर्ष के दौरान किया गया। दिसम्बर, 2015 तक निःशुल्क और इक्वीटी ऊर्जा की बिक्री के माध्यम से 1009 करोड रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

60. जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने वर्तमान जल विद्युत नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। दिसम्बर, 2015 तक सिंगल फ़ेज के 1,40,451

और 3 फ़ेज के 2,336 इलैक्ट्रो मैकेनिकल मीटरों को इलैक्ट्रानिक मीटरों से बदला गया है। ऊर्जा बचत के लिए प्रदेश के लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को 17 जनवरी, 2016 तक 41,12,754 एल.ई.डी बल्ब वितरित किए गए हैं।

61. प्रदेश में वर्तमान में 4836 सहकारी संस्थानों में 16.24 लाख सदस्य हैं। इन संस्थानों के पास 277 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी, 21,472.14 करोड़ रुपये की जमा राशि और 25,947 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी है।

62. कांग़डा, कुल्लू और शिमला जिलों में तीन नई एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है, जिस पर 81 करोड़ 70 लाख 64 ह़जार रुपये व्यय किए जा रहे हैं। सहकारी बैंकों की 466 शाखाओं ने 657.10 करोड़ रुपये के फसल ऋण आवंटित किए हैं।

63. प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में 8.98 प्रतिशत वृध्दि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में 163.14 लाख पर्यटक हिमाचल भ्रमण के लिए आए जबकि वर्ष 2015 में इनकी संख्या 177.80 लाख रही।

64. प्रदेश के कठिन, जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछ़डी पंचायतों में स्थापित की जा रही नई होटल इकाइयों को 10 वर्षों की अवधि के लिए विलासिता कर में छूट प्रदान की गई है। राज्य में रज्जू मार्ग विकसित करने के लिए इस वर्ष धर्मशाला-मैक्लोडगंज, पलचान-रोहतांग और चामुण्डा-आदी हिमानी रज्जू मार्गों के लिए समझौता हस्ताक्षरित किए गए हैं।

65. राज्य में खेल अधोसंरचना में सुधार की दिशा में बहुद्देशीय खेल परिसरों, खेल मैदानों और खेल छात्रावासों के निर्माण पर 42.75 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के अन्तर्गत अभी तक 344 खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

66. प्रदेश के प्राचीन मंदिरों में दैनिक खर्चों की जरूरतों के लिए 5 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से रिवाल्विंग फंड सृजित किया गया है। स्थानीय लोक कलाओं और पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए कुल्लू में 13.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

67. मेरी सरकार ने चकोतदारों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए योजना तैयार की है। हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के प्रावधानों को सरल बनाया गया है, ताकि निवेशकों को राज्य में विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आकर्षित किया जा सके।

68. महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निष्पादित दृष्टि बंधक उपकरण पर हिमाचल मूल के विद्यार्थियों द्वारा 7.50 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण तथा किसानों द्वारा 10 लाख रुपये तक के कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट दी गई है।

69. राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम पायलट परियोजना को तीन जिलों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है तथा अन्य चार जिलों में भी इसे कार्यान्वित करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। भूकर नक्शों के अंकरूपण

का कार्य भी प्रदेश में जारी है।

70. संसाधन जुटाने के उपायों के अन्तर्गत मेरी सरकार लोक निर्माण, वन, ऊर्जा, पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में 12023 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

71. विकास प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य में 'विकास में जन सहयोग' कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। ''विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना'' के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने 48.99 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं तथा अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले कार्य आरम्भ करने के लिए प्रत्येक विधायक को 75 लाख रुपये आबंटित किए जा रहे हैं।

72. कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के अन्तर्गत 30 दिसम्बर, 2015 तक 60,869 लाभार्थियों को 26.27 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र में 88534 श्रमिकों का पंजीकरण किया है तथा 65,738 लाभार्थियों को विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 20.25 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए गए हैं।

73. मेरी सरकार प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए दृढ संकल्प है और भ्रष्टाचार के विरूध्द शून्य सहनशीलता की नीति को अपनाया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिमला स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो में टोल-फ्री दूरभाष संख्या 0177-2629893 की सुविधा दी गई है।

74. होटल, रेस्तरां, बेकरी, ढाबा आदि चलाने वाले व्यक्ति के लिए 18 मई, 2015 से शुल्क वसूल करने की सीमा 5 लाख रुपये से ब़ढाकर 8 लाख रुपये की गई है। 25 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए एक मुश्त राशि जमा योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत कर की गणना 1 प्रतिशत दर से की जाती है। ऐसे व्यापारी, जिनकी वार्षिक रिटर्न पर उनके डिजीटल हस्ताक्षर होंगे, उन्हें 14 दिसम्बर, 2015 से अनुमानित आकलन की हार्ड कापी जमा करवाने में छूट दी गई है। उन नई औद्योगिक इकाइयों, जिन्होंने प्रथम अक्तूबर, 2015 या इसके उपरांत व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ किया है, के लिए प्रवेश कर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है।

75. लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कई ग्रामीण क्षेत्रों को नगर नियोजन अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है। अपने क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए स्थानीय शहरी निकायों को 36 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

76. वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम की 2748 बसें 2289 मार्गों पर चल रही हैं। ये बसें प्रति दिन 5.20 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लोगों को परिवहन सुविधा प्रदान कर रही हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक नई पहल करते हुए राज्य में 25 इलैक्ट्रिक बसें आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

77. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में मौसम बदलाव पर हिमाचल प्रदेश

नॉलेज सैल स्थापित कर क्रियाशील बनाया गया है। विज्ञान के रहस्योद्घाटन और आम लोगों तथा किसानों को विज्ञान एवं इसके अनुप्रयोग के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य में एक नये विज्ञान, अध्ययन एवं रचनात्मकता केंद्र की स्थापना की जा रही है। मेरी सरकार, जैव भोजन, जैव ऊर्जा, फसल सुधार, पशु पालन और जैविक कृषि जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण भी कर रही है।

78. सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों के प्रचार एवं प्रसार के लिए 'वर्चुअल मीडिया यूनिट' स्थापित की गई है।

79. माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष मेरी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि राज्य के लोगों के हित और प्रदेश को विकास एवं खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के मेरी सरकार के प्रयासों को आप अपना पूर्ण सहयोग देंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि आप सभी इस माननीय सदन की उच्च परम्पराओं को बनाए रखेंगे।

80. माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी के प्रसन्न और सफल जीवन की कामना करता हूं। मेरी सरकार की गतिविधियां आपके समक्ष रखने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने पर भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।

जय हिन्द

राष्ट्रीय गान गाया गया।

25/02/2016/1235/MS/DC/1

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 12.30 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

शोकोद्गार

25/02/2016/1235/MS/DC/2

अध्यक्ष: आज बारहवीं विधान सभा का ग्यारहवां सत्र आरम्भ होने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी मंत्रीगणों, विधायकगणों और विशेषकर सदन के नेता श्री वीरभद्र सिंह जी व विपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं सदन में माननीय सदस्यों को अपनी पूरी बात रखने का पूरा मौका दूं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप भी नियमों के अधीन रहकर समूचे प्रदेश के महत्वपूर्ण मामलों को उठाकर अपना योगदान देंगे और सदन के समय का भरपूर सदुपयोग करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की जो गरिमा पूरे देश में बनी है, उसे आप बनाए रखेंगे तथा सदन के संचालन में मुझे पूरा सहयोग देंगे। अब शोकोद्गार होंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री जी शोकोद्गार प्रकट करेंगे।

25/02/2016/1235/MS/DC/3

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मान्य सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री देसराज जी का प्रथम फरवरी, 2016 को उनके

पैतृक गांव में निधन हो गया है। यह मान्य सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री देसराज जी का जन्म 6 अप्रैल, 1950 को जिला कांगड़ा के गांव कुलाड़ा तहसील इंदौरा में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय देसराज जी वर्ष 1982 में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके उपरान्त वे प्राक्कलन समिति एवं सदन के पटल पर कागज़ात रखने संबंधी समिति के सदस्य रहे। इसके बाद वे पुनः वर्ष 1990, वर्ष 1998 व वर्ष 2007 में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उनकी सामाजिक कार्यों तथा गरीब लोगों की सेवा करने में विशेष रूचि थी। वे हमेशा ही पिछड़े तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम करते थे। यह मान्य सदन स्वर्गीय श्री देसराज जी द्वारा इस प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह मान्य सदन दिवंगत आत्मा की शांति व उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो और दो घटनाएं हुई हैं जिसमें चार लोग शहीद हुए हैं उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

25.2.2016/1240/**जेएस/एस**/1

मुख्य मंत्री:----------**जारी**---------

अध्यक्ष महोदय, पठानकोट ऑप्रेशन में हवलदार, संजीवन कुमार, शाहपुर जिला कांगड़ा से, सिपाही श्री जगदीश चन्द, जो भटियात चम्बा से थे। ये दोनों पठानकोट ऑप्रेशन में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए और इसी तरह से अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के अन्दर लांस नायक ओम प्रकाश, गांव शिखर शिमला तथा कॉंस्टेबल, आर0के0 राणा, सी0आर0पी0एफ0 जोगिन्द्रनगर मण्डी से थे उन्होंने भी अपना अन्तिम बलिदान दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा इनके परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो चार ज़वान शहीद हुए हैं,

उनके परिवार को सरकार ने 20-20 लाख रूपये श्रद्धासुमन के रूप में भेजे हैं।

25.2.2016/1240/**जेएस/एस**/2

अध्यक्ष: प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान इस सदन के चार बार सदस्य रहे श्री देस राज जी का 01 फरवरी, 2016 को निधन हो गया। वे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गंगथ विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, उसके बाद 1990 में, 1998 में और 2007 में भी वे विधान सभा में आए। वे अनेकों समितियों के सदस्य रहे। वे एक सज्जन, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे। बीच में वे वित्तायोग के अध्यक्ष भी रहे। पिछले कुछ दिनों से वे अस्वस्थ चल रहे थे और 01 फरवरी, 2016 को उनका निधन हो गया। मैं अपनी ओर से और अपने विधायक दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत के परिवार को इस सदमें को सहने की शक्ति दें।

अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कहा कि दो पठानकोट और दो जम्मू-कश्मीर के ऑप्रेशन में यानि चार हिमाचली शहीद हुए हैं। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं केवल चार हिमाचली ही नहीं अन्य लोग भी जो पठानकोट में और अन्य ऑप्रेशन्ज में शहीद हुए हैं, उन सभी सैनिकों को जो हमारे अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिक हैं, देश में लड़ते हुए कुर्बान हुए हैं, हम उन सब को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी के परिवारों को इस सदमें को सहने की शक्ति दें। इसी तरह से अन्य लोग भी राष्ट्र भक्ति से परिपूर्ण हो कर देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद।

25.2.2016/1240/**जेएस/एस**/3

अध्यक्ष: श्री कौल सिंह ठाकुर जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज बड़े ही दुख का विषय है कि हमारे सहयोगी श्री देस राज जी, जो चार बार इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं, वे आज इस संसार में नहीं हैं। वे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, हंसमुख थे और समाज सेवक थे। सदन में भी उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। उन्होंने इस सदन में रचनात्मक भूमिका निभाई है। वे इस सदन के सदस्य थे और मैं विधान सभा का अध्यक्ष था। कई मामलों को लेकर वे अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते थे। वे प्रश्नों के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से उन सब बातों को विधान सभा के अन्दर बड़े अच्छे तरीके से रखते थे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

25.02.2016/1245/SS-AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागत:

हमें जब यह पता लगा कि 1 फरवरी, 2016 को उनका निधन हुआ तो प्रदेश के अंदर एक मायूसी छा गई। उनके निधन से एक अच्छा राजनीतिज्ञ हमने खोया है जो विधान सभा के अंदर और बाहर एक रचनात्मक भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं। क्योंकि वे विधान सभा के अंदर हमारे सहयोगी रहे हैं मैं भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं और भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले और उनके परिजनों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, धन्यवाद।

समाप्त

25.02.2016/1245/SS-AG/2

अध्यक्ष: अब श्री सतपाल सिंह सत्ती शोकोद्गार में भाग लेंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री देस राज जी के स्वर्गवास होने पर जो शोकोद्गार प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखा है मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 1 फरवरी, 2016 को हमारे इस माननीय सदन के सदस्य रहे आदरणीय देस राज जी का स्वर्गवास हुआ। मुझे भी उनके साथ तीन बार विधायक रहने का मौका मिला। वे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे। एक सामान्य परिवार से उठकर इस माननीय सदन का चार बार सदस्य बनना उनकी कर्मठता और समाज के प्रति उनकी लगन को दर्शाता है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार और संबंधियों को इस दुःख को सहन करने की भगवान् शक्ति दे। माननीय मुख्य मंत्री जी और विपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने जैसे जानकारी दी कि इस देश की रक्षा के लिए अनेक सैनिक और अर्द्ध-सैनिक बलों के नौजवान व अधिकारी पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में शहीद हुए हैं मैं इस माननीय सदन में अपने दल की ओर से भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि वे उनको अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिवार को जो क्षति हुई है भगवान् उन्हें इस क्षति और दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस तरह के देशभक्त जब हमारे बीच से जाते हैं तो एक नयी प्रेरणा देश के नौजवानों को मिलती है। वह प्रेरणा देश के सब नौजवान/नागरिक उनसे लें ताकि उसी तरह से राष्ट्रभक्ति के साथ सब अपना काम करें। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी, धन्यवाद।

समाप्त

25.02.2016/1245/SS-AG/3

अध्यक्ष: अब श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री शोकोद्गार में भाग लेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों ने अपने उद्गार व्यक्त किये हैं इन सभी देशभक्तों को और जो अभी हाल ही के ऑपरेशन में और खासकर जे0एंड के0 में शहीद हुए हैं चाहे वह हवलदार संजीवन कुमार शाहपुर (कांगड़ा) से थे, वे तो मेरी अपनी रैजीमैंट के थे; चाहे सिपाही जगदीश चंद, भटियात के थे; लांस नायक, ओम प्रकाश, गांव शिखर (नजदीक चायल), शिमला के थे; कॉंस्टेबल, आर0के0 राणा, सी0आर0पी0एफ0, सरकाघाट के थे और ये स्पेशल फोर्सिस खासकर कमांडो ऑपरेशन में प्रवीण थे, इस माननीय सदन में मैं भी इन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि सभी की ओर से देना चाहूंगा। इस अवसर पर जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इन्हें विशेष आर्थिक पैकेज दिया है उसकी मैं जहां सराहना करता हूं वहां इस माननीय सदन और पूरे देशवासियों को ज़रूर कहना चाहूंगा कि कभी-कभी माननीय सदस्यों, इनके परिजनों या इनकी किसी ऑर्गेनाईजेशन की कुछेक डिमांडस आ जाती हैं हम किसी-न-किसी रूप से उन्हें कभी अनदेखा न करें।

जारी श्रीमती के0एस0

25.02.2016/1250/**केएस/एजी**/1

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जारी---

क्योंकि यह राष्ट्रभक्ति जो आपके सामने है, चाहे वह किसी प्रकार की मुसीबत हो, वह पानी के द्वारा हो, प्राकृतिक आपदा हो या man maid creation हो, सबको सम्भालने के लिए इन सैनिकों ने हमेशा अपना अदम्य साहस और देशभक्ति का परिचय दिया है इसलिए उनके गौरवपूर्ण इतिहास को हमेशा ध्यान में रखा जाए। मैं एक बार फिर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । सरकार की तरफ से उनके परिवारों को सहायता दी गई है और मैं एक बार फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार हमेशा इन शूरवीरों के साथ खड़ी है। धन्यवाद।

25.02.2016/1250/**केएस/एजी**/2

श्री मनोहर धीमान: आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री देस राज जी ने एक लम्बी बीमारी के बाद 01 फरवरी, 2016 को सुबह 9.00 बजे अपने निवास स्थान कुलाड़ा में अन्तिम सांस ली। श्री देस राज जी माननीय सदन के चार बार सदस्य रहे हैं। वे बहुत ही सरल स्वभाव के व मृदुभाषी इन्सान थे। राजनीति में उन्होंने एक ईमानदार नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि

उनके जाने से परिवार में जो क्षति हुई है उसको सहन करने का उनको बल मिले, ताकत मिले। अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए जो उन्होंने सेवाएं दी है उनको हमेशा याद रखा जाएगा।

इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, जो हिमाचल के चार सपूत शहीद हुए हैं उनके चरणों में भी मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

25.02.2016/1250/**केएस/एजी**/3

श्री रविन्द्र सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक श्री देस राज जी के निधन पर इस माननीय सदन में जो शोक प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर रखा हैं, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और मुख्य मंत्री महोदय ने भी बताया, देस राज जी बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार थे। पूरे क्षेत्र में, पूरे कांगड़ा में उनकी एक ईमानदार छवि रही। वे एक सच्चे समाज सेवक थे और अपने क्षेत्र के विकास की विभिन्न योजनाओं को लेकर माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रियों के साथ उनका मिलना और उनको हल करवाना लगातार उनके प्रयास में रहा है । आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। जब हम धूमल जी के साथ उनके घर शोक प्रकट करने के लिए गए थे तो वह दृश्य देखने वाला था, उस समय सैंकड़ों लोग उनके घर में इकट्ठा हुए थे। किसी भी व्यक्ति के इस दुनिया से जाने के बाद पता लगता है कि लोगों का उसके प्रति रुझान कैसा था और वह उस समय उनके घर में देखने को मिल रहा था। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शान्ति प्राप्त हो और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में और देश में अन्य जगहों पर हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सिज़ के जवानों ने, सैनिकों ने व सेना के अधिकारियों ने आतंकवाद को सामने रखते हुए जो

अदम्य साहस दिखाया, उनको भी हम नमन करते हैं और साथ में उनके परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

25.02.2016/1250/**केएस/एजी**/4

अध्यक्ष: स्वर्गीय देस राज जी, पूर्व सदस्य, हि0प्र0 विधान सभा के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इस माननीय सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.2.2016/1255/av/as/1

शोकोद्गार------ क्रमागत

अध्यक्ष ------- जारी

साथ ही, पठानकोट में उग्रवादियों के हमले में जो भारतीय सेना में हमारे हिमाचल प्रदेश तथा देश के दूसरे जवान शहीद हुए हैं मैं आपके साथ मिलकर उनको भी श्रद्धाजंलि देना चाहता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले

तथा हम उनसे मार्गदर्शन लें कि हम अपने राष्ट्र को ऊंचा रखने के लिए हमेशा तैयार रहें। हमारे बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, उनके लिए हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दिवंगत आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आप सभी अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(सदन में बैठें सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हो गए।)

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अब सदन के नेता द्वारा वक्तव्य होगा। माननीय मुख्य मंत्री मान्य सदन को इस सप्ताह की कार्यसूची से अवगत करवायेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मान्य सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्य सूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार से है :-

वीरवार	25 फरवरी, 2016	शासकीय / विधायी कार्य
शुक्रवार	26 फरवरी, 2016	(1) शासकीय / विधायी कार्य (2) अनुपूरक बजट प्रथम एवं अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष 2015-16 -प्रस्तुतीकरण।

25.2.2016/1255/av/as/2

अध्यक्ष : अब इस मान्य सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2016 के 11.00

बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

सुन्दर सिंह वर्मा
सचिव

शिमला-171004
दिनांक : 25/2/2016